चुनाव में इंटरनेट

डिजिटल तकनीक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इसका प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है. एक ओर जहां इससे सेवा और सूचना की उपलब्धता सुगम हुई है, वहीं झूठी खबरों और अफवाहों का खतरनाक सिलसिला भी बना है. देश-दुनिया के अनुभवों को मद्देनजर यह जरूरी हो जाता है कि चुनाव जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सूचना तकनीक की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास हो, ताकि मतदाताओं के डिजिटल डेटा की सुरक्षा भी हो सके और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी न हो सके. आज यह एक स्थापित तथ्य है कि बड़ी तकनीकी कंपनियां उपभोक्ताओं के डेटा का विश्लेषण कर उन्हें राजनीतिक तौर पर प्रभावित करने की कोशिश में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगी हुई हैं. पश्चिमी लोकतंत्रों में आज यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. हमारे देश में भी ऐसे प्रयोगों के उदाहरण सामने आ चुके हैं. यदि ऐसा फिर से होता है, तो यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह हो सकता है. दूसरी चुनौती झूठी खबरों और अफवाहों की है. हालिया अध्ययनों से इंगित होता है कि युवाओं का बड़ा हिस्सा समाचारों के लिए वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर निर्भर करता है. पिछले कुछ सालों से स्मार्टफोन की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी है तथा सस्ती दरों पर इंटरनेट का दायरा भी विस्तृत हुआ है. यह संतोष की बात है कि चुनाव आयोग ने इंटरनेट की खूबियों और खामियों को ध्यान में रखते हुए कुछ कदम उठाये हैं. राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सोशल मीडिया से आपत्तिजनक और विवादास्पद चीजों को हटाने का निर्देश देने के साथ आयोग ने बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से बैठक कर उनके साइटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए रणनीति तैयार की है. आज हमारे देश में 46 करोड़ से अधिक इंटरनेट प्रयोक्ता हैं. इसका एक मतलब यह है कि करीब 90 करोड़ मतदाताओं में से ज्यादातर किसी-न-किसी रूप में ऑनलाइन माध्यमों से सूचना पाने की स्थिति में हैं. इस चुनाव में उम्मीदवारों और पार्टियों को सोशल मीडिया के जरिये किये गये प्रचार के खर्च का हिसाब भी देना होगा. बंबई उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से मतदान के दो दिन पूर्व सोशल मीडिया पर पैसे देकर राजनीतिक या चुनावी सामग्री के प्रकाशन को रोकने के बाबत जवाब मांगा है. इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इंटरनेट बहुत बड़ा है और वहां कुछ ही समय में सूचनाएं फैल जाती हैं. सोशल मीडिया और साइटों के जरिये झूठ और भ्रामक बातें फैला कर मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकना चुनाव आयोग के लिए आसान काम नहीं है. यदि मतदाताओं के साथ-साथ पार्टियां और उम्मीदवार खुद सजग रहें तथा तकनीकी कंपनियां अपने स्तर पर सक्रिय रहें, तो आयोग को बड़ी मदद मिल सकती है. सोशल मीडिया के लिए कंपनियों की सलाह से आयोग ने जो आचार संहिता तैयार की है, उसका जोर-शोर से प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि लोगों में भी जागरूकता पैदा हो सके.

करोड़ से अधिक इंटरनेट प्रयोक्ता हैं. करीब 90 करोड़ मतदाताओं में से ज्यादातर किसी-न-किसी रूप में ऑनलाइन माध्यमों से सूचना पाने की स्थिति में हैं.

आइए, वोट करें और देश गढ़ें

चुनाव किसी भी लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता हैं. इसलिए इसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है. इसकी खूबसूरती यह है कि हर खासोआम के वोटों से सरकार का चयन होता है. इसलिए मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ माने जाते हैं. हर शख्स को यह समझना चाहिए कि उसके वोट का कितना महत्व है. यही वजह है कि प्रभात खबर ने मतदाताओं को जागरूक और प्रेरित करने के लिए वोट करें, देश गढ़ें अभियान छेड़ा हुआ है. विसंगतियों के बावजूद दुनियाभर में लोकतांत्रिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है. अतः हम सब का दायित्व है कि हम चुनाव में भागीदार बनें और वोट कर लोकतंत्र को समृद्ध करें. चुनावों में हरेक एक वोट की अहमियत है. ऐसे कई अवसर आये हैं कि एक वोट के कारण सरकारें चली गयीं हैं और लोग चुने जाने से वंचित रह गये हैं.

बहुत पुरानी बात नहीं है. केवल एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर चुकी है. 1999 में केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार थी और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे. अन्नाद्रमुक का नेतृत्व दिवंगत जयललिता के हाथों में था. केंद्र सरकार से अन्नाद्रमुक ने अपना समर्थन वापस ले लिया. इसके बाद सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाया गया. भाजपा गठबंधन के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती थी. केवल एक वोट की कमी की वजह से अटल जी की नेतृत्व वाली 13 महीने पुरानी भाजपा गठबंधन सरकार इस चुनौती को पार नहीं कर पायी. सरकार के विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 269 और विरोध में 270 वोट डाले गये थे. दूसरा मामला कांग्रेस के नेता सीपी जोशी का है. 2008 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव था. जोशी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे व मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे. वह विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ एक वोट से हार गये और उनकी दावेदारी भी खत्म हो गयी. सीपी जोशी को 62,215 और उनके प्रतिद्वंद्वी कल्याण सिंह चौहान को 62, 216 वोट मिले थे. पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कहा जाता है कि उस चुनाव में जोशी की मां, पत्नी और ड्राइवर वोट नहीं डालने नहीं गये थे. अगर ये लोग वोट डालने गये होते, तो तस्वीर कुछ और ही होती.

उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, 2004 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव था और जनता दल (यूनाइटेड) की ओर से के कृष्णामूर्ति मैदान में थे. उनका मुकाबला कांग्रेस के आर ध्रुवनारायण से था, लेकिन कृष्णामूर्ति सिर्फ एक वोट से चुनाव हार गये. उन्हें 40751 वोट और ध्रुवनारायण को 40752 वोट मिले. इस मामले में भी कहा जाता है कि कृष्णमूर्ति ने ड्राइवर को वोट डालने जाने नहीं दिया था. 2015 में पंजाब के मोहाली नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस की कुलविंदर कौर रागी ने अपनी प्रतिद्वंदी निर्मल कौर को सिर्फ एक वोट से हरा कर जीत हासिल की थी. मुंबई नगर निगम के चुनाव किसी विधानसभा चुनावों से कम नहीं होते. 2017 के चुनाव में वार्ड 220 से शिव सेना के सुरेंद्र बगलकर और भाजपा के अतुल शाह के बीच मुकाबला था. दोनों द को बराबर 5946 वोट मिले हैं. फैसला लॉटरी से हुआ और अतुल शाह विजयी हुए. सुरेंद्र बगलकर के पक्ष में अगर एक वोट और पड़ गया होता, तो तस्वीर कुछ और ही होती. लब्बोलुआब यह है कि आपका दिया एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करता है.

आशुतोष चतुर्वेदी
प्रधान संपादक, प्रभात खबर
ashutosh.chaturvedi@prabhatkhabar.in

भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक मिसाल है. हमें इसे और मजबूत करना है. कई बार एक वोट से सरकारें चली गयीं हैं और लोग चुने जाने से वंचित रह गये हैं. आइए, हम सब प्रतिज्ञा करें कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे.

चिंता का एक और विषय है कि अब जनता से जुड़े विषय चुनावी मुद्दे नहीं बनते. किसानों की समस्याएं, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की स्थिति, राज्यों का विकास जैसे विषय उभर कर सामने नहीं आ पाते हैं. पिछले लोकसभा चुनावों में हिंदी पट्टी में भाजपा का दबदबा रहा है और वह दूसरा कार्यकाल हासिल करना चाहती है. दूसरी ओर कांग्रेस अपनी वापसी करना चाहती है. यही वजह है कि दोनों पार्टियों के लिए ये लोकसभा चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गये हैं. चुनाव के मुद्दों पर नजर डालें, तो शुरुआत विकास के मुद्दे से हुई थी, लेकिन जल्द यह मुद्दा पीछे छूटता नजर आ रहा है. राहुल गांधी राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख रूप से उठा रहे हैं. कांग्रेस जीएसटी और नोटबंदी जैसे मुद्दे उठा रही है, वहीं भाजपा पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सरकार के विकास कार्यों का हवाला दे रही है. पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सघन प्रचार के जरिये भाजपा हवा का रुख अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय फैक्टर पार्टियों के गणित पर असर डाल सकते हैं.

हर सब जानते हैं कि संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है. संविधान निर्माताओं ने ऐसी परिकल्पना की थी कि संसद के माध्यम से कानून बनेंगे और उनके द्वारा जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जायेगा. सदन सार्थक चर्चा और जनता की समस्याओं के निराकरण का मंच भी है. सांसद जनहित के मुद्दों को उठाते हैं और सरकार को जवाब देना होता है. यह सारी प्रक्रिया हम सबके लिए महत्वपूर्ण है. एक तथ्य और जान लीजिए कि संसद की कार्यवाही हमारे आपके द्वारा जमा किये टैक्स से चलती है. इसको चलाने में जो लंबा चौड़ा खर्चा आता है, उसकी पूर्ति हमारे आपके टैक्स के भुगतान से की जाती है. संसद की प्रति मिनट कार्यवाही पर औसतन ढाई लाख रुपये का खर्च आता है. एक दौर था, जब संसद में विभिन्न विषयों पर लंबी और गंभीर बहसें होती थीं. यह बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन अब उनका अभाव साफ नजर आता है. एक तो अनेक सांसद सदन के विधायी नियमों का पालन नहीं करते हैं और बहुत से अवसरों पर उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं होती. एक और चिंतनीय विषय है कि सदन में अमर्यादित आचरण और शब्दों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. विधानसभाओं की स्थिति तो और भी चिंताजनक है. वहां विधायकों में मारपीट तक की घटनाएं घटित होने लगी हैं. पिछली बार एक पुरुष सांसद अपने राज्य को विशेष दर्जे की मांग को लेकर महिला का वेष धारण कर संसद भवन परिसर पहुंच गये थे. ऐसी नौटंकी लोकतंत्र के लिए कतई मुफीद नहीं है. इस सबके लिए हम और आप जिम्मेदार है, क्योंकि हम श्रेष्ठ लोगों का चयन ही नहीं करते हैं. यह जान लीजिए, जैसा बीज रोपियेगा, वैसी ही फसल काटनी पड़ेगी. इसलिए एक तो मतदान अवश्य करें. दूसरे, ऐसे व्यक्ति का चयन करें, जो क्षेत्र का विकास कर सके और आपकी समस्याओं को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठा सके. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक मिसाल है. यही वजह है कि लोकसभा चुनावों पर देश और दुनिया दोनों की निगाहें लगी हुई हैं. हमें इसे और मजबूत करना है. आइए, हम सब प्रतिज्ञा करें कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे.

खतरनाक हैं चीन के बड़े प्रोजेक्ट

प्रो सतीश कुमार
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
singhsatis@gmail.com

चीन की सबसे बड़ी पारियोजना सीपीइसी है, जो ओबीओआर योजना का कोहिनूर हीरा है. अगर अमेरिका और भारत मिल कर इस परियोजना के लिए संकट पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो चीन की नींद उड़ सकती है.

अमेरिका ने यह माना है कि चीन का ओबीओआर प्रोजेक्ट दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक है. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि दुनिया के कई देशों में चलाये जा रहे चीन के ओबीओआर और अन्य परियोजनाएं अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की बजाय उन देशों की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जायेगा. दरअसल, चीन जानबूझ कर ही ऐसा कर रहा है. दिखावटी तौर पर चीन का दावा है कि मध्य एशिया, मध्य-पूर्व, पूर्वी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ेगा. साथ ही सांस्कृतिक आयाम भी जुटेंगे, जो सिल्क रूट के युग में था. इस सोच के आधार पर पूरी विश्व व्यवस्था बदलेगी और हिंसा और संघर्ष में कमी आयेगी. ऐसा चीन का दावा है. लेकिन पश्चिम के तमाम विद्वान चीन की बात से सहमत नहीं हैं. उनकी नजर में यह एक फंदा है, जो कई देशों को फांस देगा. इसके कई उदाहरण मौजूद हैं. दरअसल, चीन इतना पैसा खर्च कर देता है कि संबंधित देश कर्ज के बोझ में दब कर समर्पण कर बैठते हैं. मलेशिया के प्रधानमंत्री ने चीन की परियोजना को धूर्त कह कर संबोधित किया. श्रीलंका में जब हंबनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका सरकार द्वारा 99 वर्षों के लिए गिरवी रखा गया, तो इसका कारण भी आर्थिक बोझ ही था. बंदरगाह के पूरी तरह से चीन के कब्जे में आने के बाद वह उसका उपयोग अपने सैनिक समीकरण को बनाने में करता है. नेपाल और पाकिस्तान में भी चीन यही कर रहा है.

पाकिस्तान की राजनीति और व्यवस्था को समझनेवाले हुडबॉय का मानना है कि बलूचिस्तान में चीन की कंपनी और उसके लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तकरीबन बारह हजार से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक लगे हुए हैं. आखिर पाकिस्तान को क्या लाभ मिलनेवाला है, जब परियोजना का पूरा फायदा चीन की कंपनी को जाता है? इससे पाकिस्तान की जनता भी नाराज है और वह चीन-विरोधी भी बन रही है. चीन तो सेना और बंदूक की नोक पर सीपीइसी (चीन-पाक आर्थिक गलियारा) योजना को चलाने में सफल है. बहुत हद तक चीन अपने पैसे के बूते नेपाल में भी घुसपैठ कर वहां की संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहा है. चीन की चाल अब भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं रहा. पिछले दिनों इटली भी चीन के घेरे में फंसता हुआ दिखायी दिया. वहीं यूरोप के देश अमेरिका से नाता तोड़कर चीन के ओबीओआर प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए व्याकुल हैं.

यहां महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि चीन की परियोजना क्या सचमुच दुनिया के लिए खतरा है? चीन की विचारधारा ही उसकी आर्थिक व्यवस्था को संचालित करती है. कहने के लिए प्राइवेट कंपनियां इसमें शामिल हैं, लेकिन उनकी सोच और कार्यप्रणाली चीन की राजनीति शक्ति से चलती है. चीन दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो अंतरराष्ट्रीय नियमों पर नहीं, बल्कि चीन की हिदायत और निर्देश पर चलती हो. चीन यूरोप को भी दो खंडों में बांट देना चाहता है. जिससे उसकी पकड़ छोटे यूरोप के देशों पर आसानी से बन सके. भारत के पड़ोसी देशों के बीच चीन पर्ल ऑफ स्ट्रिंग के जरिये भारतीय उपमहाद्वीप के देशों पर अपनी पकड़ बना ली है.

भारत ओबीओआर परियोजना का हिस्सा नहीं है. लेकिन होना या न होना भारत के लिए पर्याप्त नहीं है. जिस तरीके से चीन का अश्वमेध घोड़ा दौड़ लगा रहा है, उसे रोकना या चुनौती देना भी भारत के लिए जरूरी है. संभव है कि इस द्वंद्व में युद्ध की स्थिति भी बन सकती है. इसका उदाहरण पाकिस्तान है. भारत के प्रधानमंत्री ने कारगर कूटनीति के द्वारा महज पाकिस्तान को ही नहीं, चीन को भी घेरने की कोशिश की है. मसूद अजहर पर सुरक्षा परिषद् की सोच एक है. चीन पर निरंतर दबाव बनाया जा रहा है, जो चीन के लिए भी मुश्किलें पैदा करेगा.

भारत अब अमेरिका के साथ मिल कर चीन को घेरने की कवायद में है. चीन की सबसे बड़ी पारियोजना सीपीइसी है, जो ओबीओआर योजना का कोहिनूर हीरा है. अगर अमेरिका और भारत मिल कर इस परियोजना के लिए संकट पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो चीन की नींद उड़ सकती है. पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिये ही चीन मध्य-पूर्व एशिया और अफ्रीका तक पैर फैलाने की योजना को पूरा करना चाहता है. पाकिस्तान इसलिए भी यहां चीन की कमजोर कड़ी है, जिसके लिए वह कोई भी अधर्म कर सकता है. अगर चीन के अश्वमेध घोड़े को यहीं पर रोका नहीं गया, तो भारत का कश्मीर और अरुणाचल का हिस्सा चीन की विस्तृत नीति के नजर में होगा. वर्षों से चीन मानता आ रहा है कि यह हिस्सा चीन का है. चीन की परियोजना दरअसल सामरिक सोच का ही नतीजा है. दुनिया को जोड़ने की आड़ में वह विश्व को अपनी दलान बनाना चाहता है. इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा.

अभी तक की बात करें, तो परिस्थिति भारत के अनुकूल है, भारत और अमेरिका मिल कर चीन की दीवार को लांघ सकते हैं. इसकी शुरुआत पाकिस्तान से की जा सकती है. इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच सहमति भी बन चुकी है. अमेरिका जिस तेवर के साथ चीन से बात कर रहा है, वह भारत के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा कर रही है. भारत में एक मजबूत सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की सोच भी चीन को चुनौती देने की है. ऐसे में उम्मीद पूरी है कि भारत और अमेरिका मिल कर ही चीन की इन गतिविधियों को रोक सकते हैं.

आपके पत्र

प्रभावशाली प्रियंका !

प्रियंका गांधी के राजनीति में खुल कर आने से निश्चित ही पार्टी में नयी जान आ गयी लगती है, क्योंकि पार्टी अब उन्नीस से इक्कीस ही नहीं, उससे भी कहीं आगे जा सकती है. अयोध्या में दिया गया उनका चुनावी भाषण बहुत प्रभावशाली था. सभी पार्टियों में कुछ युवाओं नेताओं की होड़-सी लगी है, जो अच्छी बात है. प्रियंका गांधी युवा नेत्री हैं. उनका व्यक्तित्व स्वर्गीय इंदिरा गांधी से काफी मेल खाता है. समय बदल गया है, लेकिन जनता उन्हें आज उसी छवि में देखती है. शालीनता और सही भाषा से ही मुद्दों को उठाने के कारण वह और अधिक प्रभावशाली और आकर्षक होती जा रही हैं. ऐसा लगता है कि भविष्य में वह अपने भाई से भी आगे निकल सकती हैं. अन्य नेताओं को प्रियंका से बहुत कुछ सीखा चाहिए. आशा है, प्रियंका अपनी कार्य शैली से प्रभावित करती रहेंगी.

वेद मामूरपुर, नरेला

अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता

भारत एंटी-सैटेलाइट मिसाइल तकनीक का घरेलू उपयोग करने के अलावा यदि चाहे तो इसका अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक उपयोग भी कर सकता है. पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में काफी विस्तार हुआ है. मंगलयान मिशन की सफलता के बाद भारत सरकार ने गगनयान मिशन को मंजूरी दी है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी अंतरिक्ष में ले जायेगा. इसरो ने 102 उपग्रह मिशन को भी अंजाम दिया है. इसमें संचार उपग्रह, भू-पर्यवेक्षण उपग्रह, नौ-संचालन उपग्रह और अनेक प्रायोगिक उपग्रह शामिल है. भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम देश की सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है. अब उपग्रहरोधी मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि वह अंतरिक्ष में अपने संसाधनों और संपदा की रक्षा करने में पूर्ण सक्षम है. वैज्ञानिकों की इस सफलता पर हम सभी को हमेशा गर्व रहेगा.

डॉ हेमंत कुमार, भागलपुर

विभागों में मैनपावर की कमी

देश का हर विभाग कर्मचारियों का कमी झेल रहा है. वह चाहे सेवा क्षेत्र हो, न्यायिक क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र मैनपावर की कमी का शिकार है. तभी तो सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को सरकार को आदेश देना पड़ा कि 14 दिनों के भीतर न्यायाधिकरणों में रिक्त पदों की नियुक्तियां की जाए. मैनपावर की कमी के चलते देश में कार्यरत विभिन्न न्यायाधिकरण एकदम पंगु बन कर रह गये हैं. अगर यह न्यायाधिकरण देश में नहीं होते, तो अदालतों में आज जो तीन करोड़ मामले लंबित हैं, वह शायद और अधिक होते. सरकारी हठधर्मिता के आगे अब सुप्रीम कोर्ट भी लाचार हो चला है, क्योंकि इसी अदालत ने 22 साल पहले ही तमाम न्यायाधिकरणों को एक ही मंत्रालय यानी कानून और न्याय मंत्रालय के मातहत लाने का आदेश दिया था, मगर कुछ नहीं किया गया. अब एक पखवाड़े के अंदर रिक्त पदों को भरने को कहा गया है, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि देश इस समय चुनाव के मोड में है. सरकार को ट्रिब्यूनल्स के क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करना होगा.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

बोधि वृक्ष

प्रेम श्रद्धा

जब भी कभी प्रेम या श्रद्धा का भाव गहरा उठेगा, तो उससे हमारे शरीर के भीतर शक्ति का जागरण होना शुरू हो जायेगा. जो व्यक्ति पहली बार ध्यान में बैठने लगा है, उसके लिए तो सीधा बैठना आवश्यक है. अगर पहले से ही आश्रम में आये हैं, भाव है, प्रेम है, और पहले से ही दर्शन-लाभ, प्रेम-लाभ जो हो रहा है, उससे मन की स्थिति तो अच्छी हो ही जाती है. मन की स्थिति जब अच्छी होगी, तो फिर ध्यान में भी जब आप बैठते हैं, तो सहजता से गहराई हो जाती है. ध्यान की स्थिति में मन शांत हो जाता है. हमें शिथिलता या टोटल रिलैक्सेशन सिर्फ नींद में ही होती है. इसी कारण से ध्यान में जब भी साधक को ऐसे स्थिति आती है, तो यही लगने लगता है- जैसे कहीं शायद हम नींद में चले गये थे, पर वह नींद नहीं है. क्योंकि नींद की सबसे बड़ी निशानी यह होगी- एक बाहर से आवाज आपको सुनायी देनी बंद हो जायेगी. दूसरा शरीर आलस में आयेगा, तो गर्दन बाएं-दाएं लुढ़केगी. नींद में शरीर की एक जैसी स्थिति नहीं रहती. परंतु जब ध्यान में मन गहरे उतरता है, मन एकाग्र होता है, मन के विचार जब पूरे थमने लग जाते हैं, तो विचारों के पूरी तरह से थमते ही एक पूर्ण रिलैक्सेशन, शरीर में और मन में पूरी तरह से शिथिलता आ जाती है. जिसके कारण से नींद जैसा एहसास आता है, पर निश्चित रूप से वह नींद नहीं होती है. लेकिन ऐसा कुछ बुद्धि से समझने की चेष्टा करने लगेंगे, तो बुद्धि तो चक्कर में फंस ही जायेगी. तो चक्करों से मुक्ति के लिए बेहतर है कि जब भी कभी कुछ ऐसी अनुभूति हो तो सजग रहें. अपनी तरफ से बहुत विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. हार्दिक गहरी श्रद्धा भी अपने आप में एक प्रकार का ध्यान ही है. जिनके अंदर ऐसी गहरी श्रद्धा और ऐसा गहरा प्रेम उजागर हो जाता है, वे अपने आप में यूं समझिए कि बिना किये हुए ही ध्यान जैसी स्थिति में रहते हैं. इसी कारण से ध्यान करने पर जो किसी के शरीर में अनुभूतियां उठती हैं, वे उनको सहज से ही अनुभव में आने लग जाती हैं.

गुरु मां आनंदमूर्ति

कुछ अलग

सतत फूलाय नमः !

आलोक पुराणिक
वरिष्ठ व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

अप्रैल-फूल विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में चालू विश्वविद्यालय ने इस निबंध को प्रथम पुरस्कार विजेता घोषित किया है-

अप्रैल-फूल में दो शब्द होते हैं, एक अप्रैल और दूसरा फूल. फूल गुलाब का भी होता है गेंदे का भी. गुलाब के फूल की डिमांड का मौसम 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे के आसपास रहता है, पर अप्रैल वाले फूल का मौसम बारह महीनों रहता है, खासकर चुनाव में तो अप्रैल वाले फूल का जलवा ही अलग होता है.

नेता यूं तो आम तौर पर पब्लिक को बारह महीने फूल ही समझता है, पर चुनाव के ठीक पहले इस फूल को खास फूल बनाया जाता है. रोटी कपड़ा और मकान के प्रॉमिस पुराने हो गये हैं. अब तो सैटेलाइट, हर घर के सामने एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन. घसौंडा नामक कांस्टीट्यूएंसी से खड़े एक पहलवान ने घोषणा की है कि उसके गांव में बिकनेवाले आइटमों पर जीएसटी नहीं लगेगा, गांव में पंद्रह एयरपोर्ट होंगे. ऐसी घोषणाओं के फूलपन अगर पहलवानजी को कोई याद दिलाये, तो पहलवानजी कहते हैं कि अगर फूल ही बनाना है, तो बड़ा वाला बनाओ. छोटा-मोटा फूल बनाने का क्या फायदा है.

अप्रैल वाले फूल की एक खासियत यह होती है कि यह फूल बनने के लिए तैयार ही नहीं, बल्कि प्रतिबद्ध तक होता है. दरअसल, यह बात औसत फूल की तमाम गतिविधियों को देखकर समझी जा सकती है. फूल जो सीरियल देखता है, उसमें नागिन और चुड़ैल मार मचाये रहती हैं. फूल इन सीरियलों को हिट करा देता है. जो चुड़ैलों को हिट करा दे, नेताओं को उनसे बहुत उम्मीद हो जाती है, यह तो हमें भी हिट करा देगा. चुड़ैल भी हिट होती हैं और नेता भी. फूल एक चुड़ैल से दूसरी पर चला जाता है, एक नेता से दूसरे पर चला जाता है, पर उसका बुनियादी फूलपन कम नहीं होता.

भारत में फूलपुर एक लोकसभा कांस्टीट्यूएंसी का नाम भी है. कहा जा सकता कि संपूर्ण भारत ही फूलपुर है. फूल से फूल मिलते हैं, तो मामला फूलपुर का हो जाता है. फूल ना पूछता कि जो नेता कल तक राष्ट्रवादी पार्टी का प्रचंड समर्थक था, वह रातों-रात कतई घणा कांग्रेसी कैसे हो गया? फूल के अगाध फूलपन पर नेताओं को परम अगाध भरोसा होता है, और जैसा कि पहले बताया गया है कि फूल निराश नहीं करता.

लोकतंत्र में फूल महोत्सव सतत चलते हैं. लोकसभा चुनाव निपटे, तो विधानसभा चुनाव आ लेते हैं. विधानसभा चुनाव निबटे, तो कहीं-कहीं नगर निगम चुनाव और पंचायती चुनाव भी आ लेते हैं. मतलब हर सीजन में कहीं-ना-कहीं कोई फूल बन ही रहा होता है. इसलिए तो परम विद्वान संपूर्ण भारत को फूलपुर घोषित करते हैं. जिसमें हर कहीं फूल बनने और फूल बनाये जाने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं.

अगर कोई एक अप्रैल को अप्रैल फूल कहे, तो उसे जवाब दिया जाना चाहिए कि हम तो सतत फूल बनते हैं, सतत फूलाय नमः ! तो फिर आइए संपूर्ण फूलपुर के निवासी परस्पर एक-दूसरे को कहें- सतत फूलाय नमः !

देश दुनिया से

सऊदी अरब को परमाणु तकनीक की मंजूरी मिली

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब को परमाणु तकनीक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अमेरिका के ऊर्जा मंत्री रिक पेरी ने अमेरिकी कानून निर्माताओं को बताया कि अमेरिकी कंपनियों ने सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी बेचने से जुड़े जो छह आवेदन दिये थे, उन्हें अब मंजूरी मिल गयी है. पेरी ने सीनेट की आर्म्ड सर्विस कमेटी को बताया कि ऊर्जा विभाग ने जनवरी 2017 से लेकर अब तक करीब 37 परमाणु आवेदनों को मंजूरी दी है, जिनमें से नौ मध्य पूर्व से हैं. इसके अलावा छह सऊदी अरब से, तो दो जॉर्डन से जुड़े हैं. सऊदी को मिली मंजूरी को लेकर अब अमेरिकी संसद में सवाल उठ रहे हैं कि जिस देश पर मामूली हथियारों के मामले में भरोसा नहीं कर सकते, उस पर परमाणु मामलों में भरोसा करना कितना सही है? संसदीय समिति की बैठक के दौरान पेरी से पूछा गया कि क्या ये आवेदन बीते साल दो अक्तूबर के बाद यानी सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद दिये गये हैं. इस पर पेरी ने कहा कि उन्हें एकदम सटीक डाटा नहीं पता है. गौरतलब है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद सऊदी अरब को परमाणु प्रौद्योगिकी दिये जाने को लेकर अपनी चिंता जताते रहे हैं.

कार्टून कोना

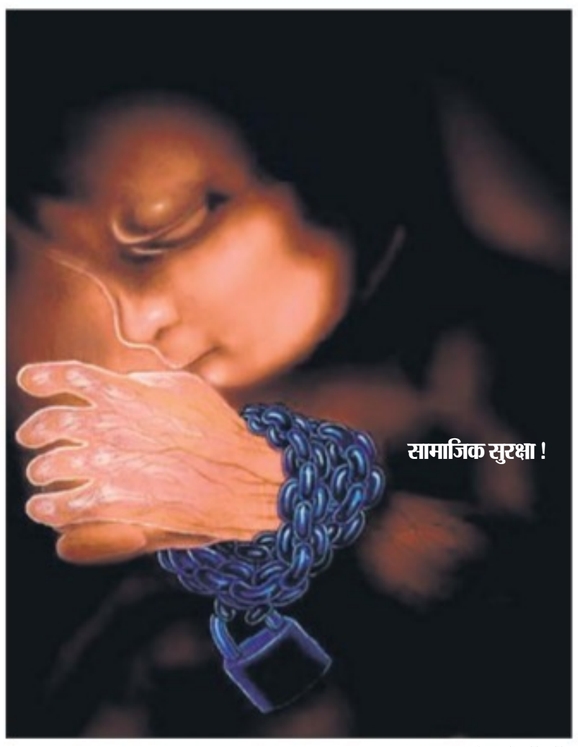

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है